बाजार थामने को चीनी होगी आयात

कच्ची चीनी आयात के फैसले से उत्तरी राज्यों की चीनी मिलों में बेचैनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने बृहस्पतिवार को तीन लाख टन चीनी आयात करने का फैसला किया है। इससे घरेलू बाजार में चीनी मूल्य में होने वाली वृद्धि पर अंकुश पाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह फैसला जहां उपभोक्ताओं को राहत दे सकता है, वहीं उत्तरी राज्यों की मिलों की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

सरकार का यह फैसला दक्षिणी राज्यों में सूखे से हलकान चीनी मिलों के हित में उठाया गया है। तमिलनाडु व कर्नाटक में सूखा पड़ने की वजह से गन्ने की फसल बहुत खराब हो गई है। लिहाजा मिलों में पेराई कम हो जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 24.2 फीसद अधिक होने वाला है। चीनी उद्योग के मुताबिक अक्तूबर से चालू होने वाली पेराई सीजन में चीनी का कुल उत्पादन 251 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि एक अक्टूबर को चीनी का शुरुआती स्टॉक 40 लाख टन होगा। चीनी की यह स्टॉक घरेलू जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है।

25 फीसद शुल्क पर तीन लाख टन कच्ची चीनी का होगा आयात

40 लाख टन होगा एक अक्तूबर को चीनी का ओपेनिंग स्टॉक

251 लाख टन होने का अनुमान है पेराई सीजन में चीनी का कुल उत्पादन

इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर दक्षिणी राज्यों की चीनी मिलों की मांग को देखते हुए सरकार ने तीन लाख टन कच्ची चीनी के आयात का फैसला किया है। कच्ची चीनी का आयात करने अधिकार केवल दक्षिण भारत की चीनी मिलों को दिया गया है। ओजीएल लाइसेंस के तहत आयातित चीनी पर 25 फीसद का आयात शुल्क लगाया जाएगा। कच्ची चीनी का आयात केवल दक्षिणी बंदरगाहों पर ही किया जा सकेगा। इनमें तूतीकोरन, कराइकल, चेन्नई, मंगलौर, काकीनाड़ा, गंगावरम और विशाखापट्टनम को नामित किया गया है। डीजीएफटी ही कच्ची चीनी आयात के बारे में निर्धारित नियमों का पालन करायेगी।

तमिलनाडु में गन्ने का रकबा कम होने से वहां की मिलें केवल अपनी क्षमता का केवल 25 फीसद ही पेराई कर सकेंगी। जबकि कर्नाटक की मिलें अपनी पेराई क्षमता का 40 फीसद पेराई कर सकेंगी। आयातित कच्ची चीनी को उपलब्ध गन्ने के रस में मिलाकर दक्षिणी राज्यो की मिलों को चलाया जा सकता है। दक्षिणी राज्यों में चीनी की उपलब्धता बनाये रखने और मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की मिलों ने कच्ची चीनी आपूर्ति का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ढुलाई खर्च अधिक होने इसे खारिज कर दिया गया। आयातित चीनी घरेलू चीनी के मुकाबले बहुत सस्ती उपलब्ध होगी।

Dainik Jagaran

8/9/2017